

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 115/2024

प्रशान्त कुमार

—अपीलार्थी

## बनाम

- शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोंही।
- खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिरोंही, जिला सिरोंही।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 05.03.2024

आदेश की दिनांक : 06.03.2024

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- लेखराज तोसावड़ा, सदस्य  
असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

- मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
- अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत पाडीव पंचायत समिति सिरोंही में दिनांक 14.12.2017 (अनुलग्नक-1) हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हालीवाड़ा, पंचायत समिति सिरोंही, जिला सिरोंही में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.09.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पंचायत फुंगणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ग्राम पंचायत जैला में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है (अनुलग्नक-3)। राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार किसी भी कर्मचारी को 3 वर्ष पूरे होने से पहले स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण पिछले 3 वर्षों में 4 बार किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हालीवाड़ा, पंचायत समिति सिरोंही, जिला सिरोंही में कार्य करने दिया जायें।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हालीवाड़ा, पंचायत समिति सिरौही, जिला सिरौही में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ग्राम पंचायत जैला में प्रशासनिक दृष्टि से राज्यहित में किया गया। यहां तक तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer order issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
6. आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य